



डिफेंस कॉरीडोर उत्तर प्रदेश

सुझावों हेतु सार्वजनिक परामर्श के लिए आमंत्रण

फरवरी, 2018 में लखनऊ में आयोजित हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर से 20,000 करोड़ रुपये का निवेश और 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की सम्भावना के उद्देश्य से है। प्रमुख रक्षा विनिर्माण नोडों की पहचान आगरा, अलीगढ़, झांसी, जालौन, चित्रकूट और कानपुर के रूप में की गई है।

अतः यूपीडा आम जनता, लाभार्थियों एवं हितधारकों को डिफेंस कॉरिडोर पर उनके बहुमूल्य सुझाव एवं टिप्पणी प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है। इस परियोजना के संभावित निवेशकों को दी गई विशेष रियायतें इस प्रकार हैं।

- लॉजिस्टिक पार्क/ परिवहन केन्द्र एवं बंदरगाहों से आयातित संयंत्रों के राज्य के उत्पादन केन्द्रों तक परिवहन व्यय में 50 प्रतिशत धनराशि की अधिकतम सीमा रु. 2 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति।
- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य के उत्पादन केन्द्रों से लॉजिस्टिक पार्क/परिवहन केन्द्रों तथा बंदरगाहों तक संयंत्रों की दुलाई पर 30 प्रतिशत की सीमा में अधिकतम रु. 1 करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति।
- प्रथम 5 वेंडर्स और लंगर इकाइयों को प्रौद्योगिकी अंतरण की लागत की 75 प्रतिशत और अगले 5 उत्पादनकर्ता को 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 50 लाख की प्रतिपूर्ति
- रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में R&D या परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु 5 वर्ष की अवधि में होने वाले पूजा निवेश व्यय की अधिकतम सीमा रु. 2 करोड़ प्रति निवेश तक 50 प्रतिशत राशि का अनुदान।
- प्रचलित सर्किल दरों या लागत मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर परिकलित एंकर इकाइयों को भूमि लागत की 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति।

आप हमारे ईमेल आईडी :- ce2.eida-up@gov.in पर अपने सुझाव/टिप्पणियां प्रेषित कर सकते हैं
या

उन्हें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:-

सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

बुंदेलखंड डिफेन्स कॉरिडोर

सुझावों हेतु सार्वजनिक परामर्श के आमंत्रण विषयक

फरवरी, 2018 में लखनऊ में आयोजित हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए **माननीय प्रधान मंत्री** ने यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए वायदे के क्रम में बुंदेलखंड में एक डिफेन्स कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। प्रस्तावित डिफेन्स कॉरिडोर से 20,000 करोड़ रुपये का निवेश और 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। प्रमुख रक्षा विनिर्माण नोडों की पहचान आगरा, अलीगढ़, झांसी, जालौन, चित्रकूट और कानपुर के रूप में की गई है।

अतः यूपीडा आम जनता (लाभार्थियों एवं हितधारकों) को डिफेन्स कॉरिडोर पर उनके बहुमूल्य सुझाव एवं टिप्पणी प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है। इस परियोजना के अंतर्गत संभावित निवेशकों को दी गई विशेष रियायतें इस प्रकार हैं।

- राज्य में उत्पादन के स्थान पर रसद पार्क / परिवहन केंद्रों और बंदरगाह / बंदरगाह से आयातित उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के परिवहन पर अधिकतम INR 2 करोड़ तक, 50% लागत की परिवहन सब्सिडी।
- वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए यूनिट से रसद पार्क / परिवहन केंद्र, बंदरगाह / बंदरगाह तक तैयार उत्पादों के परिवहन पर अधिकतम INR 1 करोड़ तक की 30% लागत की परिवहन सब्सिडी।
- पहले 5 विक्रेताओं की ओर एंकर इकाइयों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत का 75% और अगले 5 विक्रेताओं की ओर 50% की प्रतिपूर्ति, प्रत्येक विक्रेता इकाई के लिए अधिकतम INR 50 लाख के अधीन।
- एकल खिड़की- रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों को सभी आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी राज्य की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से एक छत के नीचे प्रदान की जाएगी जो सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।
- रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आर एंड डी या परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए, अधिकतम निवेश 2 करोड़ रुपये तक पूंजीगत निवेश पर 5 साल के लिए 50% सब्सिडी, शर्तों के अधीन।
- एंकर इकाइयों को भूमि लागत की 25% प्रतिपूर्ति प्रचलित सर्कल दरों या लागत मूल्य के आधार पर गणना की जाती है, जो भी कम हो।